

## अवरुद्ध मुद्रास्फीति एवं RBI की मौद्रिक नीति

### प्रलम्ब के लिये:

[भारतीय रिज़र्व बैंक](#), [रेपो रेट](#), [मुद्रास्फीति](#), [केंद्रीय बजट](#), [अवरुद्ध मुद्रास्फीति](#)

### मेन्स के लिये:

भारत में आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में ब्याज दर का महत्त्व

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

[भारतीय रिज़र्व बैंक](#) (RBI) ने अपनी नवीनतम [द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा](#) में [मुद्रास्फीति लक्ष्य](#) एवं [आर्थिक वृद्धि](#) पर चर्चा के बीच लगातार [आठवीं बार रेपो दर को अपरविरतित](#) बनाए रखने का विकल्प चुना है।

### RBI की ब्याज दरों में कमी क्यों नहीं?

- **अवरुद्ध मुद्रास्फीति (Persistent Inflation):** उच्च रेपो दर होने पर भी मुद्रास्फीति वर्ष 2021 की शुरुआत से 4% के स्तर तक नहीं पहुँची है। यह गरिबत धीरे-धीरे हुई है, वर्ष 2024 के पहले चार महीनों में मुद्रास्फीति 5% के आस-पास रही। RBI "अवरुद्ध" मुद्रास्फीति के रुझान के प्रति चिंतित है।
- **अवरुद्ध मुद्रास्फीति नियंत्रण (Durable Inflation Control):** RBI का लक्ष्य स्थिरता पर नियंत्रण रखना है, न कि 4% से नीचे हुई अस्थायी गरिबत पर। RBI गवर्नर द्वारा 4% के लक्ष्य को "अवरुद्ध आधार पर" प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।
- **मजबूत जीडीपी वृद्धि:** भारत का [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) विकास आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रहा है, जो लगातार चार वर्षों से 7% से अधिक है। RBI ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। इस परिदृश्य में, रेपो दरें संभवतः आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही हैं।
- **आगामी केंद्रीय बजट:** RBI आगामी [केंद्रीय बजट](#) पर विचार कर रहा है, जो मुद्रास्फीति की गतिशीलता के साथ ही मौद्रिक रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है।

# मौद्रिक नीति समिति

## Monetary Policy Committee

### मौद्रिक नीति समिति

#### ★ प्राधिकरण:

- ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।

#### ★ उद्देश्य:

- ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

### मौद्रिक नीति समिति (MPC)

#### ★ कानूनी ढाँचा:

- ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत।
  - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- ★ MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

### संघटन

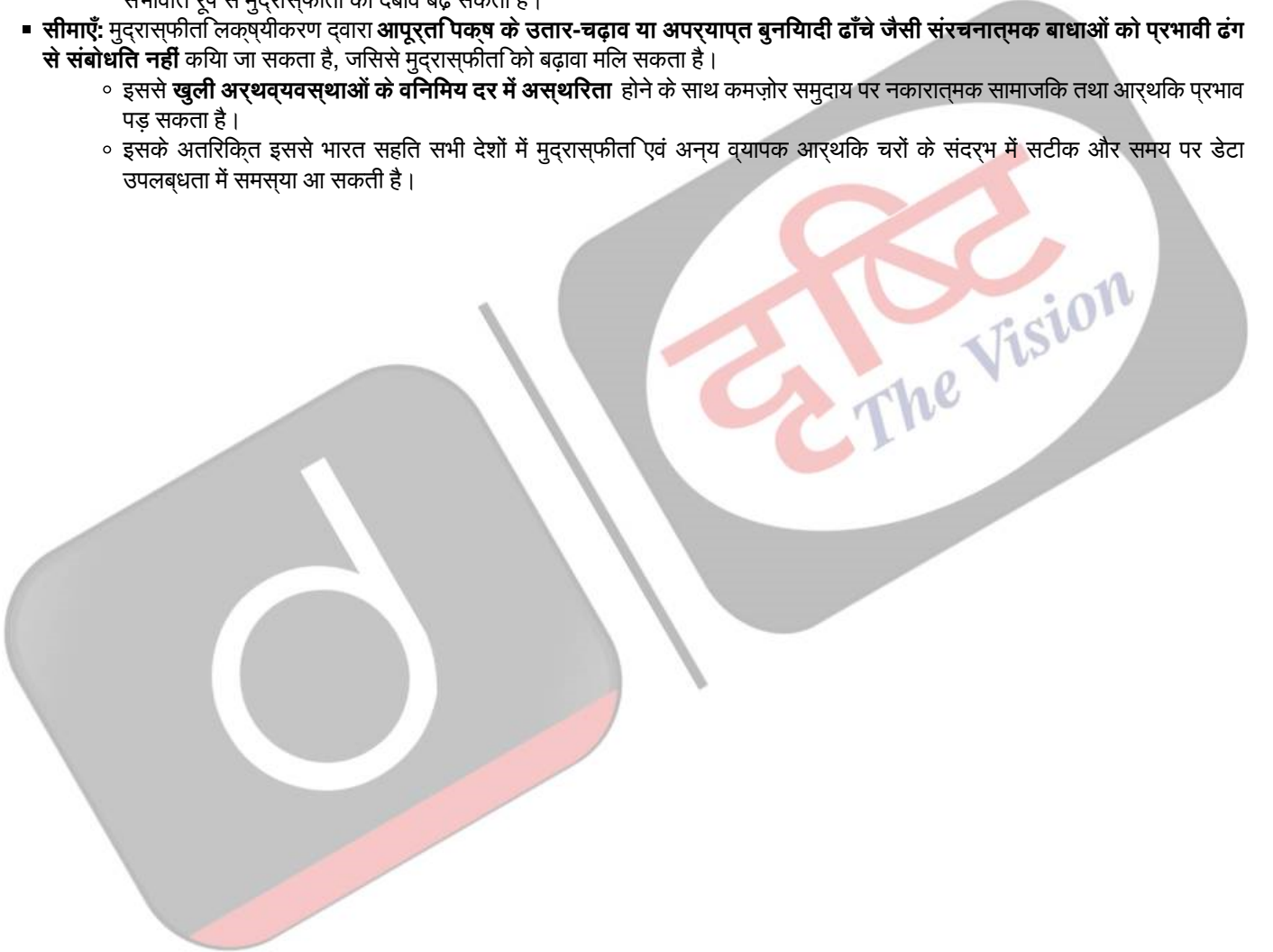
- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

### कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
  - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
  - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार RBI को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6-18 महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

## RBI का मुद्रास्फीतिलक्ष्य क्या है?

- **परिचय:** RBI की मुद्रास्फीतिलक्ष्य निर्धारण एक मौद्रिक नीति ढाँचा है जिसे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये क्रियान्वित किया जाता है।
  - RBI ने एक विशिष्ट मुद्रास्फीतिलक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में **4% प्रतविरष निर्धारित** है। यह लक्ष्य एक दीर्घकालिक औसत है और कोई कठोर सीमा या न्यूनतम सीमा नहीं है।
  - लक्ष्य के साथ **+/- 2 प्रतिशत अंकों की सहनशीलता सीमा** भी है। इसका अर्थ है कि RBI मुद्रास्फीतिको तब तक स्वीकार्य मानता है जब तक यह 2% से 6% के दायरे में रहती है।
- **उद्देश्य:** मुद्रास्फीतिलक्ष्यीकरण का **मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्राप्त करना तथा उसे बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रुपए के मूल्य की रक्षा करना एवं अर्थव्यवस्था में उचित संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना** है।
- **प्रणाली:** RBI द्वारा मुद्रास्फीतिको प्रभावित करने के लिये मौद्रिक नीति उपकरण (मुख्य रूप से रेपो दर) का उपयोग किया जाता है।
  - रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है।
  - रेपो दर बढ़ाकर **RBI से ऋण लेना अधिक महँगा होने से खर्च एवं निवेश हतोत्साहित होता है**, जिससे अंततः मुद्रास्फीति में कमी आती है।
  - इसके विपरीत रेपो दर को कम करने से ऋण एवं खर्च को प्रोत्साहन मिलने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है लेकिन इससे संभावित रूप से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।
- **सीमाएँ:** मुद्रास्फीतिलक्ष्यीकरण द्वारा **आपूर्ति पक्ष के उतार-चढ़ाव या अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसी संरचनात्मक बाधाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं** किया जा सकता है, जिससे मुद्रास्फीतिको बढ़ावा मिल सकता है।
  - इससे **खुली अर्थव्यवस्थाओं के वनिमिय दर में अस्थिरता** होने के साथ कमज़ोर समुदाय पर नकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।
  - इसके अतिरिक्त इससे भारत सहित सभी देशों में मुद्रास्फीति एवं अन्य व्यापक आर्थिक चरों के संदर्भ में सटीक और समय पर डेटा उपलब्धता में समस्या आ सकती है।



# मौद्रिक नीति की मात्रात्मक लिखतें

## QUANTITATIVE INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY



### ₹ चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

- रेपो दर (RR): वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यहाँ, RBI प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
- रिवर्स रेपो दर: वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रेपो दर के विपरीत।
- यदि RBI सख्त मौद्रिक नीति का संकेत देना चाहता है, तो वह रेपो दर में वृद्धि करेगा; बैंक अपनी उधारी दरों में वृद्धि करेंगे।

### 📈 बैंक दर

- यह एक दीर्घकालिक दर है (रेपो दर अल्पकालिक है) जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है।
- बैंक दर में वृद्धि से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि होगी और इसी तरह इसमें कमी से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में कटौती होगी।

### 📄 सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

- SLR जमाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी है जो वाणिज्यिक बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है।
- यदि RBI मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है, तो वह SLR में वृद्धि करेगा।

### 🏦 नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक है।
- CRR में वृद्धि के साथ ही बैंक ऋण की दरों में वृद्धि कर देते हैं।



### खुला बाजार परिचालन (OMOs)

- इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।



Drishiti IAS

## अवरुद्ध मुद्रास्फीति:

- **परिचय:** अवरुद्ध मुद्रास्फीति का आशय एक ऐसी क्रमिक आर्थिक घटना से है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आपूर्ति तथा मांग की गतिशीलता में परिवर्तन के साथ त्वरति रूप से समायोजित नहीं होती हैं।
  - आमतौर पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें, जिनकी त्वरति रूप से कम होने की संभावना नहीं होती है उन्हें अवरुद्ध माना जाता है।
  - इस "अवरुद्धता" के कारण मुद्रास्फीति को वांछित स्तर (जैसे कि भारत में RBI का 4% का लक्ष्य) पर वापस लाना मुश्किल हो जाता है।
- **अवरुद्ध मुद्रास्फीति की विशेषताएँ:** आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद कीमतें उच्च बनी रहती हैं। चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षा एवं आवास जैसे कुछ क्षेत्र विशेष रूप से अवरुद्ध मुद्रास्फीति से ग्रस्त हैं।
  - इससे आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की **क्रय शक्त क्षमता में कमी** आती है।
  - इससे प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की संभावना के बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंकों के लिये समस्याएँ आती हैं।
- **अवरुद्ध मुद्रास्फीति के कारण:** अपरिवर्ती मूल्य निर्धारण तंत्र जैसे कारकों के कारण कीमतें, बाज़ार की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से तुरंत प्रभावित नहीं होती हैं।
  - वेतन में वृद्धि से व्यवसायों की लागत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति अवरुद्ध होती है।
  - स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट स्थितियों सतत/नरंतर मुद्रास्फीति में योगदान करती हैं।
- **अवरुद्ध मुद्रास्फीति का प्रबंधन:** केंद्रीय बैंक अमूमन मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिये ब्याज दरें बढ़ाते हैं, हालाँकि आर्थिक मंदी से बचने के लिये दर समायोजन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - अवरुद्ध मुद्रास्फीति का सामना कर रहे विशिष्ट क्षेत्रों को संबोधित करने वाली लक्षित नीतियाँ इसके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।
  - अवरुद्ध मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये आर्थिक पूर्वानुमानों और नीतियों का नियमित मूल्यांकन तथा समायोजन महत्त्वपूर्ण है।

### दृष्टि भेन्स प्रश्न:

**प्रश्न.** भारत में अवरुद्ध मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिये तथा भारत में आर्थिक स्थिरता और नीति प्रबंधन पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये।

### और पढ़ें: वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????:

**प्रश्न:** भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

1. पछिले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है।
2. बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (रुपए में) में पछिले एक दशक में लगातार वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

**प्रश्न.** यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना
2. सीमांत स्थायी सुवर्धा दर को बढ़ाना
3. बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनर्तथान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sticky-inflation-and-rbi-s-monetary-policy>

